Jayoti vidyapeeth women's university, Jaipur

राजस्थान में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर आत्मनिर्भर भारत अभियान का प्रभाव: एक व्यापक विश्लेषण

शोधार्थी

गिरधारी लाल यादव

एनरोलमेन्ट नं.

JVR-I/22/10088

शोध निर्देशक

डॉ. मिनी अमित अरावतिया

वाणिज्य विभाग

पीएच.डी.

वाणिज्य

शोध उपाधि पंजीयन के लिए प्रस्तुत

सार–संक्षेप **(SYNOPSIS)**

सारांश

शीर्षकः राजस्थान में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर आत्मनिर्भर भारत अभियान का प्रभावः एक व्यापक विश्लेषण

विषयसूची

परिचय 2

साहित्य की समीक्षा 4

परिचय 4

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए वित्तीय सहायताः 5

व्यवसाय करने में आसानीः 5

डिजिटलीकरण और प्रौद्योगिकी अपनानाः 5

आपूर्ति श्रृंखला लचीलापनः 5

रोजगार सृजनः 6

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के सामने चुनौतियांः 6

पिछला साहित्य 6

अनुसंधान अंतराल 8

शोध का उद्देश्य 9

शोध का महत्व 9

परिकल्पना..........10

कार्यप्रणाली 11

संभावित अध्याय योजना 12

निष्कर्षों और सुझावों का सारांश 13

अध्ययन की सीमाएँ 13

सन्दर्भ..........14

परिचय

दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक, भारत ने लंबे समय से अपने आर्थिक परिदृश्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की महत्वपूर्ण

भूमिका को मान्यता दी है। ये उद्यम न केवल आर्थिक विकास के इंजन हैं बल्कि रोजगार सृजन, निर्यात प्रोत्साहन और गरीबी उन्मूलन में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। कोविड–19 महामारी के मद्देनजर, एमएसएमई को अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, श्रम की कमी और वित्तीय संकट शामिल हैं। इन मुद्दों को संबोधित करने और एमएसएमई के लचीलेपन को बढ़ाने के लिए, भारत सरकार ने मई 2020 (भारत सरकार, 2020) में "आत्मनिर्भर भारत अभियान" (आत्मनिर्भर भारत मिशन) शुरू किया।

आत्मनिर्भर भारत अभियान

भारत सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक राहत पैकेज का हिस्सा था। यह राशि भारत की जीडीपी का लगभग 10 प्रतिशत है। इसे चार किश्तों में जारी करने की घोषणा की गई थी जिसे रियल एस्टेट, एमएसएमई, एनबीएफसी और बिजली क्षेत्रों सहित विभिन्न क्षेत्रों में वितरित किया गया था। योजना के तहत पाँच स्तंभ थे अर्थव्यवस्था, प्रणाली, बुनियादी ढाँचा, माँग और जीवंत जनसांख्यिकी। इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था में नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए कुछ सुधारों की भी घोषणा की गई। ये थे कानूनों में स्पष्टता, कराधान में तर्कसंगत प्रणाली, कृषि आपूर्ति श्रृंखला में सुधार, कुशल मानव संसाधन और मजबूत वित्तीय प्रणाली (प्रधानमंत्री कार्यालय, 2020)।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों(एमएसएमई)

एमएसएमई का मतलब सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम है, और यह उन व्यवसायों को संदर्भित करता है जो अपने वार्षिक कारोबार या कर्मचारियों की संख्या के संदर्भ में एक निश्चित आकार सीमा के भीतर आते हैं। इसके अंतर्गत व्यवसाय वस्तुओं के निर्माण, प्रसंस्करण और सेवाओं से संबंधित हैं।

एमएसएमई का वर्गीकरण

उद्यम का आकार	वार्षिक कारोबार और निवेश
सूक्ष्म	निवेश– 1 करोड़ रुपये से कम वार्षिक कारोबार– 5 करोड़ रुपये से कम
लघु	निवेश – 10 करोड़ रुपये से कम वार्षिक कारोबार – 50 करोड़ रुपये तक
मध्यम	निवेश – 20 करोड़ रुपये से कम वार्षिक कारोबार–100 करोड़ रुपए तक का

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए प्रासंगिक आत्मनिर्भर भारत अभियान के प्रमुख घटकः

सरकार ने महामारी के दौरान परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करने के लिए एमएसएमई के लिए संपार्श्विक–मुक्त स्वचालित ऋण की घोषणा की। इसका उद्देश्य संकटग्रस्त व्यवसायों को तत्काल वित्तीय राहत प्रदान करना था। ईसीएलजीएस के तहत, एमएसएमई 29 फरवरी, 2020 तक अपने बकाया ऋण के 20 प्रतिशत तक अतिरिक्तक्रेडिट के लिए पात्र थे। इस योजना का उद्देश्य एमएसएमई को अपने परिचालन को फिर से शुरू करने में मदद करने के लिए तरलता सहायता प्रदान करना था (वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, 2020)। पीएलआई योजना का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और कपड़ा सहित विभिन्न क्षेत्रों में निर्माताओं को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करके घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है। इससे अप्रत्यक्ष रूप से एमएसएमई को उनके उत्पादों और सेवाओं के लिए मांग पैदा करके लाभ हुआ। सरकार का लक्ष्य प्रक्रियाओं को सरल बनाकर, कागजी कार्रवाई को कम करके और व्यापार करने में आसानी की सुविधा देकर एमएसएमई पर नियामक बोझ को कम करना है (भारत सरकार, 2020)। सरकार का लक्ष्य प्रक्रियाओं को सरल बनाकर, कागजी कार्रवाई को कम करके और व्यापार करने में आसानी की सुविधा देकर एमएसएमई पर नियामक बोझ को कम करना है (नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग, 2020)। अभियान ने दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार में प्रौद्योगिकी की भूमिका को पहचानते हुए एमएसएमई को डिजिटलीकरण और प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। महामारी के दौरान आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के आलोक में, अभियान ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भरता को कम करने के लिए आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन और उत्पादन के स्थानीयकरण की आवश्यकता पर जोर दिया। स्वदेशी विनिर्माण और एमएसएमई (प्रेस सूचना ब्यूरो, 2020) का समर्थन करने के लिए स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने और खरीदने पर नए सिरे से जोर दिया गया।

साहित्य की समीक्षा

परिचय

रोजगार सृजन, जीडीपी वृद्धि और निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान के कारण सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में मान्यता दी गई है। कोविड़ –19 महामारी और परिणामी आर्थिक चुनौतियों के मद्देनजर। इस महत्वाकांक्षी पहल का उद्देश्य एमएसएमई पर विशेष ध्यान देने के साथ विभिन्न क्षेत्रों को पुनर्जीवित करना है। यह साहित्य समीक्षा भारत में एमएसएमई पर आत्मनिर्भर भारत अभियान सहित सरकारी पहलों के प्रभाव का पता लगाने का प्रयास करती है, जबकि वित्तीय सहायता, व्यापार करने में आसानी, डिजिटलीकरण और आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन जैसे प्रमुख पहलुओं पर विचार करती है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए वित्तीय सहायताः

आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक महत्वपूर्ण घटक महामारी के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए एमएसएमई को वित्तीय सहायता का प्रावधान था। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) का उद्देश्य एमएसएमई को तत्काल राहत प्रदान करना है। भनोट और आनंद (2021) के एक अध्ययन के अनुसार, ईसीएलजीएस योजना ने राजस्थान में संपार्श्विक–मुक्त ऋण की पेशकश करके एमएसएमई को समर्थन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस वित्तीय जीवनरेखा ने आर्थिक अनिश्चितता की अवधि के दौरान एमएसएमई को अपना संचालन बनाए रखने, वेतन का भुगतान करने और अन्य आवश्यक खर्चों को पूरा करने में मदद की।

इसके अलावा, सरकार ने तनावग्रस्त एमएसएमई को अधीनस्थ ऋण प्रदान करने के लिए अधीनस्थ ऋण (सीजीएसएसडी) के लिए एक क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की। इस योजना ने एमएसएमई के वित्तीय स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए उनमें बहुत आवश्यक इक्विटी डालने का प्रयास किया। शर्मा और चतुर्वेदी (2020) ने कहा कि इस योजना ने दिवालियेपन और नौकरी के नुकसान को रोककर राजस्थान के एमएसएमई क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

व्यापार करने में आसानीः

आत्मनिर्भर भारत अभियान ने नियमों को सरल बनाने और एमएसएमई पर अनुपालन बोझ को कम करने पर भी जोर दिया। इस नियामक सहजता से राजस्थान में कारोबारी माहौल बढ़ने की उम्मीद थी। जैन और शर्मा (2020) के एक अध्ययन से पता चला कि राजस्थान में राज्य सरकार ने इन सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू किया, जिससे एमएसएमई के लिए व्यापार करने में आसानी में सुधार हुआ। सुधारों में प्रशासनिक प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण, कागजी कार्रवाई कम करना और अधिक कुशल व्यवसाय पंजीकरण प्रणाली जैसे उपाय शामिल थे।

डिजिटलीकरण और प्रौद्योगिकी अपनानाः

डिजिटलीकरण और प्रौद्योगिकी को अपनाना आत्मनिर्भर भारत अभियान के प्रमुख क्षेत्र थे। इस पहल का उद्देश्य एमएसएमई को अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए डिजिटल टूल और प्लेटफॉर्म अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। चक्रवर्ती (2021) ने इस बात पर प्रकाश डाला कि राजस्थान स्थित एमएसएमई, जिन्होंने सक्रिय रूप से डिजिटलीकरण को अपनाया, ने विस्तारित बाजार पहुंच, बेहतर ग्राहक जुड़ाव और अपने संचालन में दक्षता में वृद्धि जैसे लाभों की सूचना दी। "डिजिटल इंडिया" अभियान, एक पूरक पहल, ने आवश्यक बुनियादी ढाँचा और डिजिटल साक्षरता सहायता प्रदान की, जिससे एमएसएमई को डिजिटल क्षेत्र में स्थानांतरित करने में सुविधा हुई।

आपूर्ति श्रृंखला लचीलापनः

महामारी के दौरान वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान के कारण आपूर्ति श्रृंखला रणनीतियों के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ी। उत्पादन–लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना, आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक हिस्सा, घरेलू विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखला स्थानीयकरण

को प्रोत्साहित करती है। मोहन और मेनन (2021) ने पाया कि राजस्थान में पीएलआई योजना में भाग लेने वाले एमएसएमई आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों का सामना करने के लिए बेहतर ढंग से तैयार थे, जिससे अंततः उनकी लचीलापन बढ़ गई।

रोज़गार सृजन :

रोजगार सृजन आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य था, खासकर राजस्थान जैसे बड़ी श्रम शक्ति वाले राज्य में। संकटग्रस्त क्षेत्रों के पुनरुद्धार और विभिन्न योजनाओं के तहत उत्पादन के विस्तार से कुशल और अकुशल दोनों प्रकार के श्रमिकों की मांग में वृद्धि हुई। पांडे और पाठक (2020) के एक अध्ययन में राज्य में रोजगार सृजन में अभियान का उल्लेखनीय योगदान देखा गया। कपड़ा और विनिर्माण जैसे श्रम प्रधान उद्योगों में रोजगार के अवसरों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई।

एमएसएमई द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियाँः

हालाँकि सरकार की पहल का उद्देश्य एमएसएमई को बढ़ावा देना था, लेकिन वे चुनौतियों से रहित नहीं थे। वर्मा और गुप्ता (2021) ने इस बात पर प्रकाश डाला कि राजस्थान में कई एमएसएमई को जटिल आवेदन प्रक्रियाओं और पात्रता मानदंडों के कारण वित्तीय सहायता योजनाओं तक पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसने इन योजनाओं को और अधिक सरलीकरण और सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी पात्र एमएसएमई को लाभ मिल सके। इसके अलावा, डिजिटलीकरण की ओर तेजी से बदलाव ने कुछ एमएसएमई, विशेषकर राजस्थान के दूरदराज के इलाकों में डिजिटल साक्षरता और बुनियादी ढांचे की बाधाओं से संबंधित चुनौतियों का सामना किया है। इन चुनौतियों से निपटना यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि डिजिटलीकरण के लाभ राज्य के सभी एमएसएमई के लिए समावेशी और सुलभ हों।

पिछला साहित्य

पांडा (2022) ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोविड़ –19 महामारी के प्रभावों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान की। लेख एक अत्यधिक प्रासंगिक मुद्दे को संबोधित करता है – भारत में कोविड़–19 महामारी के आर्थिक प्रभाव। संकट की अभूतपूर्व प्रकृति को देखते हुए, भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुलनात्मक विश्लेषण को शामिल करने से अध्ययन में गहराई आती है। अन्य देशों के साथ भारत की आर्थिक प्रतिक्रिया की तुलना करके, लेख महामारी के दौरान भारत के सामने आने वाली चुनौतियों और अवसरों पर एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है।

खातून और इफ्फत (2022) ने भारतीय हथकरघा क्षेत्र के सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों की जांच की, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य पर विशेष ध्यान दिया गया, दोनों ही समय में कोविड़–19 महामारी के फैलने से पहले और उसके दौरान। इसके अतिरिक्त, अध्ययन ने हथकरघा बुनकरों और अन्य संबंधित मजदूरों की आजीविका बढ़ाने में आत्मनिर्भर भारत

अभियान (आत्मनिर्भर भारत मिशन) के संभावित लाभों की जांच की, जो महामारी से प्रतिकूल रूप से प्रभावित थे। डेटा इकट्ठा करने के लिए, उत्तर प्रदेश के दस अलग–अलग शहरों में कुल 400 हथकरघा बुनकरों और संबंधित व्यवसायों में व्यक्तियों के साथ टेलीफोन साक्षात्कार आयोजित किए गए। सरकारी कल्याण पहलों और इन कार्यक्रमों के अनुमानित लाभों के बारे में जागरूकता की सीमा का आकलन करने के लिए वर्णनात्मक सांख्यिकीय तरीकों को नियोजित किया गया था। अध्ययन से पता चला कि सरकारी कल्याण योजनाओं के बारे में हथकरघा बुनकरों और संबंधित श्रमिकों के बीच सीमित जागरूकता थी। जबकि कुछ को इन योजनाओं से लाभ हुआ था, एक महत्वपूर्ण अनुपात ने प्रदान की गई सहायता पर असंतोष व्यक्त किया। कोविड–19 महामारी ने इन व्यक्तियों के सामने आने वाली चुनौतियों को और बढ़ा दिया है। हालाँकि, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शुरू किए गए उपायों से बुनकरों और संबंधित श्रमिकों को उनकी खोई हुई आय वापस पाने में सहायता करने की क्षमता है।

मुखोपाध्याय, जैन और घोष (2021) ने निकट भविष्य में व्यापक आर्थिक संकेतकों पर आत्मनिर्भर पैकेज के संभावित प्रभावों का आकलन किया। यह देश के विकास पैटर्न के भीतर अलग–अलग क्षेत्रीय गतिशीलता पर प्रकाश डालता है, इस बात पर प्रकाश डालता है कि कम विकसित क्षेत्रों को सरकार के समर्थन उपायों से सीमित प्रभाव का अनुभव हो सकता है। इसके अतिरिक्त, अध्ययन बताता है कि रोजगार वृद्धि बाधित बनी हुई है, जिसके लिए भारत सरकार को अधिक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, सरकार को बुनियादी ढांचे के विकास प्रयासों के साथ–साथ श्रम–गहन विनिर्माण क्षेत्रों को प्राथमिकता देनी चाहिए। यह दृष्टिकोण अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में पिछड़े और आगे के संबंधों के निर्माण को बढ़ावा देगा, जो अंततः अधिक संतुलित और टिकाऊ आर्थिक विकास पथ में योगदान देगा। इन प्रमुख रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करके और क्षेत्रीय असमानताओं पर विचार करके, सरकार अधिक समावेशी और की दिशा में काम कर सकती है। लचीला आर्थिक सुधार

शेट्टी और भट (2022) का लक्ष्य भारतीय आर्थिक परिदृश्य के भीतर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के महत्व की जांच करना और अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए एक व्यापक ताकत, कमजोरियों, अवसरों और चुनौतियों (एसडब्ल्यूओसी) विश्लेषण का संचालन करना था। इन उद्यमों के संचालन को आकार देने वाले आंतरिक और बाह्य दोनों कारक। यह लेख एक वैचारिक अनुसंधान दृष्टिकोण का अनुसरण करता है, जिसमें विभिन्न आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त द्वितीयक डेटा को शामिल किया गया है, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) की आधिकारिक वार्षिक रिपोर्ट शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। प्रतिष्ठित अकादमिक पत्रिकाओं और प्रतिष्ठित वेबसाइटों में प्रकाशित सहकर्मी–समीक्षित शोध पत्र। यह क्षेत्र के भीतर चुनौतियों और अवसरों को स्वीकार करते हुए विकास को बढ़ावा देने, रोजगार पैदा करने और सकल घरेलू उत्पाद में योगदान करने की उनकी क्षमता पर प्रकाश डालता है। लेख एमएसएमई क्षेत्र को और मजबूत करने और इसकी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए नीतिगत पहल और समर्थन के महत्व पर जोर देता है।

पाधी (2022) ने आत्मनिर्भर भारत और व्यापार करने में आसानी ढांचे के अंतर्संबंध की जांच की। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे ये दोनों अवधारणाएं व्यापार के लिए विश्व स्तर पर आकर्षक गंतव्य बनने की भारत की खोज में एक–दूसरे की पूरक हैं। आत्मनिर्भर भारत पहल वैश्विक निवेश को प्रोत्साहित करने और लुभाने, जटिल प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और भारत को एक आकर्षक वैश्विक व्यापार केंद्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्णभूमिका निभाती है। अंतिम उद्देश्य विदेशी स्रोतों पर निर्भरता कम करना और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। यह पेपर इन पहलों के महत्व, उनके सहक्रियात्मक प्रभावों, वांछित स्थिति प्राप्त करने में आने वाली चुनौतियों और विदेशी स्रोतों पर निर्भरता को कम करने के लिए अपनाई गई रणनीतियों को रेखांकित करता है।

अनुसंधान अंतराल

अभियान के तहत शुरू की गई ईसीएलजीएस और सीजीएसएसडी जैसी वित्तीय सहायता योजनाओं ने राजस्थान में कई एमएसएमई को जीवन रेखा प्रदान की है, जिससे उन्हें कोविड़–19 महामारी से उत्पन्न आर्थिक चुनौतियों का सामना करने में मदद मिली है। हालाँकि, इन योजनाओं को निरंतर सरलीकरण और सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी पात्र एमएसएमई इन तक बिना किसी बाधा के पहुंच सकें। अभियान नियमों को आसान बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा और डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने से राजस्थान में एमएसएमई के लिए व्यापार करने में आसानी में सुधार हुआ है। फिर भी, डिजिटल साक्षरता और बुनियादी ढाँचे की कमी से संबंधित चुनौतियाँ बनी हुई हैं, खासकर दूरदराज के क्षेत्रों में। सभी एमएसएमई को समावेशी डिजिटलीकरण का लाभ सुनिश्चित करने के लिए इन अंतरों को पाटना महत्वपूर्ण है। आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन एमएसएमई के लिए एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय बन गया है, और उत्पादन–लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना ने व्यवधानों का सामना करने की उनकी क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालाँकि, पीएलआई और अन्य आपूर्ति श्रृंखला–संबंधित उपायों के दीर्घकालिक प्रभाव का आकलन करने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है।

इन जानकारियों के बावजूद, एक शोध अंतर बना हुआ है। भविष्य के अध्ययन राजस्थान में विशिष्ट नीति तंत्र और उनकी प्रभावशीलता पर गहराई से विचार कर सकते हैं। राज्य में एमएसएमई पर अभियान के दीर्घकालिक आर्थिक और सामाजिक प्रभाव का आकलन अधिक व्यापक समझ प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त, अन्य राज्यों के साथ तुलनात्मक विश्लेषण अभियान के प्रभाव में क्षेत्रीय विविधताओं को उजागर कर सकता है। निष्कर्ष में, जबकि इस व्यापक विश्लेषण ने राजस्थान में एमएसएमई पर अभियान के प्रभाव के बारे में हमारी समझ को उन्नत किया है, नीतियों को परिष्कृत करने, चुनौतियों का समाधान करने और इस महत्वपूर्ण क्षेत्र की निरंतर वृद्धि और लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए और अधिक शोध आवश्यक है।

प्राथमिक उद्देश्य भारत के राजस्थान राज्य में संचालित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) पर आत्मनिर्भर भारत अभियान के प्रभाव की व्यापक जांच करना है। भारत

सरकार द्वारा कोविड़–19 महामारी के जवाब में शुरू किया गया आत्मनिर्भर भारत अभियान, भारतीय अर्थव्यवस्था को फिर से जीवंत करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण नीति पहल का प्रतिनिधित्व करता है। इस आर्थिक परिदृश्य के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में एमएसएमई को इस पहल के तहत पर्याप्त ध्यान और समर्थन प्राप्त हुआ।

इस अध्ययन का उद्देश्य विशेष रूप से राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में एमएसएमई के विकास और लचीलेपन को बढ़ावा देने में सरकारी नीति और पहल की भूमिका में मूल्यवान अनुभवजन्य साक्ष्य और अंतर्दृष्टि प्रदान करना है।

शोध का उद्देश्य :

1. वित्तीय स्थिरता, व्यापार करने में आसानी, डिजिटलीकरण, आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन और रोजगार सृजन जैसे विभिन्न आयामों पर विचार करते हुए, राजस्थान में एमएसएमई पर आत्मनिर्भर भारत अभियान के वास्तविक प्रभाव का मूल्यांकन और मात्रा निर्धारित करना।

2. अभियान के कार्यान्वयन के दौरान राजस्थान में एमएसएमई के सामने आने वाली चुनौतियों की पहचान करना और उनका विश्लेषण करना, जिसमें वित्तीय सहायता तक पहुंचने में बाधाएं, नियामक जटिलताएं और प्रौद्योगिकी अपनाने में बाधाएं शामिल हैं।

3. अभियान के परिणामस्वरूप राजस्थान में एमएसएमई के लिए बनाए गए अवसरों का पता लगाना, जिसमें विकास, बाजार विस्तार और बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धात्मकता की संभावनाएं शामिल हैं।

4. अच्छी तरह से सूचित सिफारिशें और नीतिगत अंतर्दृष्टि प्रदान करना जो राजस्थान में सरकार, नीति निर्माताओं और एमएसएमई हितधारकों को इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के निरंतर विकास और समर्थन के लिए सूचित निर्णय लेने में मदद कर सके।

अनुसंधान का महत्व :

आत्मनिर्भर भारत अभियान एमएसएमई को समर्थन देने और कोविड–19 महामारी के मद्देनजर अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए भारत सरकार की एक प्रमुख नीतिगत पहल का प्रतिनिधित्व करता है। राजस्थान जैसे विशिष्ट क्षेत्र में इस नीति के प्रभाव का मूल्यांकन करने से इसकी प्रभावशीलता में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि मिलेगी, जो भविष्य के नीतिगत निर्णयों को सूचित कर सकती है। राजस्थान अद्वितीय आर्थिक विशेषताओं वाला एक विविध राज्य है। इस क्षेत्रीय संदर्भ में अभियान के प्रभाव का अध्ययन करने से नीति निर्माताओं को विशिष्ट क्षेत्रीय आवश्यकताओं और चुनौतियों के अनुरूप पहल करने में मदद मिलती है। अभियान विशेष रूप से श्रम–गहन क्षेत्रों में नौकरियां पैदा करना चाहता है। राजस्थान में रोजगार सृजन प्रभाव का आकलन करने से रोजगार सृजन में एमएसएमई की भूमिका के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिलती है, जो आर्थिक सुधार का एक महत्वपूर्ण पहलू है। अनुसंधान एमएसएमई के लिए व्यापार करने में आसानी के महत्व पर प्रकाश डालेगा। इस क्षेत्र में सुधार न केवल राजस्थान में बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी कारोबारी माहौल को बेहतर बना सकता है और आर्थिक विकास में

योगदान दे सकता है। अध्ययन का अनुशंसा अनुभाग नीति निर्माताओं, उद्योग संघों और स्वयं एमएसएमई के लिए कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। ये अनुशंसाएँ भविष्य के नीतिगत निर्णयों और व्यावसायिक रणनीतियों का मार्गदर्शन कर सकती हैं।

परिकल्पना

परिकल्पना 1

(एच$_0$):आत्मनिर्भर भारत अभियान ने राजस्थान में एमएसएमई की वित्तीय स्थिरता पर कोई प्रभाव नहीं डाला है।

(एच$_1$):आत्मनिर्भर भारत अभियान ने राजस्थान में एमएसएमई की वित्तीय स्थिरता पर सकारात्मक प्रभाव डाला है।

परिकल्पना 2

(एच$_0$): अभियान ने राजस्थान में एमएसएमई के लिए व्यापार करने में आसानी में कोई सुधार नहीं किया है।

(एच$_1$): अभियान ने राजस्थान में एमएसएमई के लिए व्यापार करने में आसानी में सुधारकिया है।

परिकल्पना 3

(एच$_0$): अभियान का राजस्थान में एमएसएमई क्षेत्र में रोजगार सृजन में कोई योगदान नहीं रहा है।

(एच$_1$): अभियान का राजस्थान में एमएसएमई क्षेत्र में रोजगार सृजन में योगदान रहा है।

परिकल्पना 4

(एच$_0$): राजस्थान में एमएसएमई को अभियान के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने का प्रयास करते समय बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ा है।

(एच$_1$): राजस्थान में एमएसएमई को अभियान के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने का प्रयास करते समय बाधाओं का सामना करना पड़ा है।

परिकल्पना 5

(एच$_0$): राजस्थान में एमएसएमई ने अभियान द्वारा प्रस्तुत अवसरों के कारण अपनी बाजार पहुंच का विस्तार नहीं किया है।

(एच$_1$): राजस्थान में एमएसएमई ने अभियान द्वारा प्रस्तुत अवसरों के कारण अपनी बाजार पहुंच का विस्तार किया है।

क्रियाविधि

डेटा संग्रहण

द्वितीयक डेटाः सरकारी रिपोर्ट, नीति दस्तावेज़, अकादमिक अध्ययन, उद्योग रिपोर्ट और आरबीआई और एमएसएमई मंत्रालय जैसे संगठनों से प्राप्त आकड़ोका उपयोग किया जायेगा। इस प्रकार का डेटा अभियान की नीतियों और राजस्थान में एमएसएमई के मौजूदा आर्थिक परिदृश्य की मूलभूत समझ प्रदान करेगा।

प्राथमिक डेटाः प्राथमिक मात्रात्मक डेटा इकट्ठा करने के लिए राजस्थान में एमएसएमई के बीच सर्वेक्षण होगा। एक प्रश्नावली विकसित कि जायेगी जिसमें सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता, वित्तीय सहायता का उपयोग, व्यवसाय करने में आसानी में सुधार और रोजगार सृजन पर प्रभाव जैसे प्रमुख पहलुओं को शामिल किया गया हो।

नमूना डिज़ाइनः

यह अध्ययन राजस्थान में एमएसएमई के विभिन्न क्षेत्रों, आकारों और भौगोलिक स्थानों से प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए सर्वेक्षण के लिए एक स्तरीकृत नमूना तकनीक का उपयोग किया जायेगा। यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि अनुसंधान विविध प्रकार के दृष्टिकोणों को ग्रहण करता है। राजस्थान में एमएसएमई की विविध प्रकृति को देखते हुए, जनसंख्या को विशिष्ट मानदंडों के आधार पर स्तरों या उपसमूहों में विभाजित किया जाएगा जो अभियान के प्रभाव को प्रभावित कर सकते हैं। इन मानदंडों में उद्योग का प्रकार, भौगोलिक स्थिति (शहरी बनाम ग्रामीण), व्यवसाय का आकार (सूक्ष्म, लघु, मध्यम), और संचालन के वर्ष शामिल हो सकते हैं। उपयुक्त नमूना आकार लगभग 100 एमएसएमई का होगा।

अध्ययन का समय

यह अध्ययन अध्ययन के लिए समय सीमा पर विचार करेगा, जिसमें आत्मनिर्भर भारत अभियान के कार्यान्वयन से पहले की अवधि, इसके कार्यान्वयन और इसके संचालन के बाद के वर्ष शामिल हैं। इससे अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों प्रभावों का आकलन किया जा सकता है। समय के साथ अभियान के प्रभाव के विकास को ट्रैक करने के लिए यह अनुदैर्ध्य अनुसंधान होने जा रहा है। यह दृष्टिकोण अध्ययन की तत्काल समय सीमा से परे निरंतर प्रभावों और रुझानों के आकलन की अनुमति देगा।

डेटा विश्लेषण

सर्वेक्षण डेटा के लिए, मात्रात्मक प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने के लिए वर्णनात्मक सांख्यिकीय तरीकों को नियोजित किया जाएगा। एसपीएसएस का उपयोग डेटासेट के लिए किया जाएगा, क्योंकि एसपीएसएस का व्यापक रूप से अनुसंधान में उपयोग किया जाता है और यह डेटा का पता लगाने, सारांशित करने और निष्कर्ष निकालने के लिए सांख्यिकीय परीक्षणों और प्रक्रियाओं की एक विस्तृत श्रृंखला करने की अनुमति देता है। इसमें निष्कर्षों को सारांशित करने और प्रस्तुत करने के लिए आवृत्तियों, प्रतिशत और औसत की गणना शामिल होगी। परिकल्पनाओं का विश्लेषण सांख्यिकीय उपकरण जैसे टी–परीक्षण, ची–स्क्वायर परीक्षण या प्रतिगमन विश्लेषण का उपयोग करके किया जाएगा। शोध प्रश्नों के आधार पर, डेटा में संबंधों या पैटर्न को उजागर करने के लिए प्रतिगमन विश्लेषण, एनोवा, कारक विश्लेषण या क्लस्टरिंग जैसी उन्नत सांख्यिकीय तकनीकों को नियोजित किया जा सकता है।

संभावित अध्याय योजना

राजस्थान में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) पर आत्मनिर्भर भारत अभियान के प्रभाव की व्यवस्थित रूप से जांच करने के लिए इस अध्ययन की संरचना को पांच मुख्य अध्यायों में व्यवस्थित किया गया है।

अध्याय 1: परिचय अध्ययन के महत्व, उसके उद्देश्यों और शोध प्रश्नों पर प्रकाश डालते हुए मूलभूत संदर्भ प्रदान करेगा। यह समस्या विवरण तैयार करके और राजस्थान में एमएसएमई पर अभियान के प्रभावों की जांच की आवश्यकता स्थापित करके संपूर्ण अनुसंधान प्रयास के लिए मंच तैयार करेगा।

अध्याय 2: साहित्य समीक्षा भारत में एमएसएमई, आत्मनिर्भर भारत अभियान और एमएसएमई पर सरकारी पहल के प्रभावों पर प्रासंगिक शोध के बारे में मौजूदा ज्ञान की तलाश करेगी। यह अध्याय सैद्धांतिक रूपरेखा स्थापित करेगा और विषय की वर्तमान समझ में अंतराल की पहचान करेगा।

अध्याय 3: कार्यप्रणाली अध्ययन की व्यावहारिक और निगमनात्मक प्रकृति पर जोर देते हुए अनुसंधान दर्शन, दृष्टिकोण और डिजाइन की रूपरेखा तैयार करेगी। यह सर्वेक्षण और साक्षात्कार सहित डेटा संग्रह विधियों के बारे में विस्तार से बताएगा, और नियोजित नमूनाकरण तकनीकों और डेटा विश्लेषण उपकरणों का वर्णन करेगा। शोध में नैतिक विचारों पर भी चर्चा की जाएगी।

अध्याय 4: डेटा विश्लेषण वित्तीय स्थिरता, व्यवसाय करने में आसानी, डिजिटलीकरण, आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन और रोजगार सृजन जैसे विभिन्न आयामों पर अभियान के प्रभाव का आकलन करने के लिए सर्वेक्षण डेटा का विस्तृत मात्रात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करेगा।

अध्याय 5: निष्कर्ष और चर्चा मात्रात्मक और गुणात्मक परिणामों को संश्लेषित करेगी, जो राजस्थान में एमएसएमई पर अभियान के प्रभाव का समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करेगी। अध्याय

गंभीर रूप से निष्कर्षों के निहितार्थों पर चर्चा करता है, उन्हें अनुसंधान उद्देश्यों के साथ संरेखित करता है, और अंततः इस महत्वपूर्ण विषय पर ज्ञान के भंडार में योगदान देता है।

निष्कर्षों और सुझावों का सारांश

यह अध्ययन राजस्थान राज्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) पर आत्मनिर्भर भारत अभियान के प्रभाव की व्यापक जांच पर आधारित है। सावधानीपूर्वक डेटा संग्रह और विश्लेषण के माध्यम से, अनुसंधान ने एमएसएमई संचालन के विभिन्न पहलुओं पर अभियान के प्रभाव में उल्लेखनीय अंतर्दृष्टि का खुलासा किया। वित्तीय स्थिरता एक प्रमुख आयाम के रूप में उभरी, जिसमें साक्ष्य चुनौतीपूर्ण समय के दौरान एमएसएमई को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करने में अभियान की महत्वपूर्ण भूमिका की ओर इशारा करते हैं। कोविड़–19महामारी के कारण हुआ। यह समर्थन विशेष रूप से आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) और अधीनस्थ ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएसएसडी) जैसी योजनाओं के माध्यम से स्पष्ट था, जिसने राजस्थान में एमएसएमई की वित्तीय स्थिरता में योगदान दिया।

इसके अलावा, अध्ययन ने एमएसएमई के लिए व्यापार करने में आसानी को बढ़ाने में हुई प्रगति पर प्रकाश डाला, क्योंकि नियामक सुधारों और डिजिटलीकरण पहलों ने सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं की सुविधा प्रदान की और कागजी कार्रवाई के बोझ को कम किया। आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन में भी सुधार देखा गया, उत्पादन–लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के लिए धन्यवाद, जिसने एमएसएमई की बाधाओं को झेलने की क्षमता को मजबूत किया। रोजगार सृजन, अभियान का एक सर्वोपरि लक्ष्य, आकार लेता हुआ पाया गया, विशेष रूप से श्रम–गहन में क्षेत्र। फिर भी, अध्ययन ने वित्तीय सहायता योजनाओं तक पहुंच से संबंधित चुनौतियों की पहचान की, जिनके लिए सरलीकरण और पहुंच में वृद्धि की आवश्यकता है।

निष्कर्षतः, आत्मनिर्भर भारत अभियान ने राजस्थान में एमएसएमई परिदृश्य पर एक स्पष्ट छाप छोड़ी है, जो अवसर और चुनौतियाँ दोनों प्रदान करता है। ये निष्कर्ष भारत की आर्थिक यात्रा में एमएसएमई के स्थायी महत्व को रेखांकित करते हुए, इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के विकास और लचीलेपन को और अधिक बढ़ावा देने के उद्देश्य से अच्छी तरह से सूचित नीतिगत सिफारिशों के लिए आधार प्रदान करेंगे।

अध्ययन की सीमाएँ

सर्वेक्षण का नमूना राजस्थान में एमएसएमई के विविध पूल से लिया गया था। हालाँकि, यह पहचानना आवश्यक है कि सर्वेक्षण में भागीदारी स्वैच्छिक थी, जिसने कुछ हद तक स्व–चयन पूर्वाग्रह का परिचय दिया हो सकता है। विशिष्ट विशेषताओं या अनुभव वाले एमएसएमई भाग लेने के लिए अधिक इच्छुक हो सकते हैं, जो संभावित रूप से सर्वेक्षण परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। यह अध्ययन सर्वेक्षणों और साक्षात्कारों के माध्यम से प्राप्त स्व–रिपोर्ट किए गए

डेटा पर निर्भर था। अध्ययन मुख्य रूप से राजस्थान में एमएसएमई पर केंद्रित है, जबकि इस क्षेत्रीय विशिष्टता ने अधिक गहन विश्लेषण की अनुमति दी है, यह विभिन्न आर्थिक विशेषताओं और नीति संदर्भों के साथ अन्य राज्यों या क्षेत्रों में निष्कर्षों की सामान्यीकरण को सीमित कर सकता है। सीमा पर काबू पाने के लिए, निष्कर्षों को त्रिकोणीय बनाने के लिए मात्रात्मक और गुणात्मक अनुसंधान विधियों को संयोजित करना महत्वपूर्ण है। यह दृष्टिकोण अनुसंधान विषय की अधिक व्यापक समझ प्रदान कर सकता है और विभिन्न डेटा संग्रह विधियों के माध्यम से प्राप्त परिणामों को मान्य कर सकता है। अन्य विधि अनुदैर्ध्य अनुसंधान करके अध्ययन की समय–सीमा को बढ़ाना है। यह दृष्टिकोण दीर्घकालिक रुझानों की जांच और समय के साथ नीतियों या हस्तक्षेपों के निरंतर प्रभाव के आकलन की अनुमति देता है।

संदर्भ

1. भनोट, एस., और आनंद, ए. (2021)। भारत में एमएसएमई पर कोविड–19 का प्रभाव और सरकारी राहत उपाय। जर्नल ऑफ़ पब्लिक अफेयर्स, ई2694.

2. चक्रवर्ती, एस. (2021)। भारत में डिजिटल परिवर्तन और एमएसएमईः सरकारी पहल के प्रभाव का विश्लेषण। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड रिसर्च, 8(5), 49–56.

3. भारत सरकार. (2020)। आत्मनिर्भर भारत अभियानः व्यापक आर्थिक पैकेज https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1622243

4. भारत सरकार. (2020)। आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1674263

5. जैन, एस., और शर्मा, एम. (2020)। व्यवसाय करने में आसानी की दिशा में सरकार की पहल और भारत में एमएसएमई पर उनका प्रभाव। ई–बिजनेस, मार्केटिंग और उपभोक्ता मनोविज्ञान में उभरते रुझानों का ग्लोबल जर्नल, 6(3), 140–149।

6. खातून, एस., और इफ्फत, ए. (2022)। आत्मनिर्भर भारत अभियानः उत्तर प्रदेश हथकरघा क्षेत्र को पुनर्जीवित करने का एक उपकरण। कपड़ा और परिधान अनुसंधान जर्नल, 26(4), 468–484।

7. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। (2020)। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आर्थिक पैकेज। https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1624012से लिया गया

8. मोहन, एस., और मेनन, एस. (2021)। भारतीय एमएसएमई में आपूर्ति श्रृंखला लचीलापनः सरकारी प्रोत्साहन की भूमिका। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ऑपरेशंस एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट, 41(5), 675–695।

9. मुखोपाध्याय, के., जैन, के., और घोष, पी.पी. (2021)। तरलता प्रवाहः ई3–इंडिया मॉडल का उपयोग करके आत्मनिर्भर पैकेज का आकलन। भारत में क्षेत्रीय नीतियों का अर्थव्यवस्था–व्यापी मूल्यांकनः ई3–भारत मॉडल के अनुप्रयोग, 323–378।

10. नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (नीति आयोग), (2020)। आत्मनिर्भर भारत अभियानः रिकवरी का नेतृत्व करने के लिए एमएसएमई को सशक्त बनाना। https://niti.gov.in/sites/default/files/2021-02/AatmanirbharBharatAbhiyanReport.pdfसे लिया गया

11. पाधी, एन. (2022) आत्मनिर्भर भारत और ईओडीः भारत में उनका अंतर्संबंध और प्रभाव। व्यवसाय प्रशासन, 124.

12. पांडा, पी.के. (2022)। भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोविड–19 का आर्थिक प्रभावः एक तुलनात्मक विश्लेषण। कोविड–19 के बाद के युग में ऊर्जा और बुनियादी ढांचा प्रबंधन, 41।

13. पांडे, पी., और पाठक, पी. (2020)। एमएसएमई में रोजगार सृजन पर सरकारी पहल का प्रभावः आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक अध्ययन। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट इन्वेंशन, 9(11), 68–74।

14. प्रेस सूचना ब्यूरो, (2020)। 13 क्षेत्रों के लिए उत्पादन–लिंक्ड प्रोत्साहन योजना को मंजूरीः 5 वर्षों में 1.97 लाख करोड़ रुपये प्रदान किए जाएhttps://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1661606से लिया गया

15. प्रधान मंत्री कार्यालय (2020)। पीएम मोदी ने कुल 20 लाख करोड़ रुपये के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1622369से लिया गया

16. शेट्टी, एम.ओ., और भट्ट, जी. (2022)। भारतीय एमएसएमई का प्रदर्शन विश्लेषण। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एप्लाइड इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट लेटर्स (आईजेएईएमएल), 6(2), 197–216।

17. वर्मा, आर., और गुप्ता, एन. (2021)। सरकारी वित्तीय सहायता योजनाओं तक पहुँचने में एमएसएमई के सामने आने वाली चुनौतियाँः राजस्थान का एक केस स्टडी। उद्यमिता और लघु व्यवसाय के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल, 43(2), 245–261।